HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 38—HLA OF 2022

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2022. Short title.

2. After clause (4A) of section 2 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:- Amendment of section 2 of Haryana Act 16 of 1994.

"(4B) 'core area' means built-up area within the municipal limit planned or developed fifty years before the coming into force of this amendment Act and which due to urbanization and efflux of time require replanning of land use and also includes built-up area of village abadi, which has subsequently been included in municipal limit;".

3. For sub-section (2) of section 346 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 346 of Haryana Act 16 of 1994.

"(2) The Director shall not later than six months from the date of declaration under sub-section (1), or within such further period as the Government may allow, prepare plans showing the controlled area and core area and signifying therein the nature of restrictions and conditions proposed to be made applicable to the controlled area and submit the plans to the Government :

Provided that the mixed land use shall be permitted in core area subject to the planning parameters and payment or recovery of such charges, as may be notified by the Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, there are provisions to notify controlled area in and around municipal limits. Further, to regulate the haphazard development around municipal towns, there is provision in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 for declaration of controlled area and publication of development plan for such controlled area. The area within the municipal town is governed and regulated by Haryana Municipal Corporation Act, 1994. For the purpose of integrated planning of the area, the proposals of controlled areas and development plans notified under the provisions of Act of 1963 are adopted within the municipal limit under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

With the above setup of controlled areas and development plans, the town existing is shown in the development plan with different terms like 'Existing Town/Core Area/Old Town' etc. Since, the existing town had been developed in haphazard manner, hence no land use is defined for the "Existing town" in the Development Plan. Moreover, where controlled area was declared around the existing municipal limit, the vacant areas within the said municipal limit, were assigned various land uses in the Development plans, which are only advisory in nature as provisions of Act of 1963 are not applicable in that area.

Further, the existing town or core area, which is basically mixed land use area, has neither been defined in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 nor in Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Conventionally municipalities approve the building plans considering mixed nature of land uses in core areas, but the core area has not been defined in any Act. As such, there is no clarity on the core area and mixed land uses. This has caused confusion with respect to the development plan proposals applicable in such areas called with various terminologies i.e. Old Area/ Core Areas/ Original municipal limit etc.

Therefore, to clarify the confusion, there is necessity to define the 'Core Area' by carrying out amendment in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 by inserting the definition of core area and providing provision related to mix land use in the core area.

KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 25th December, 2022.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 25th December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

Extract from the Haryana Municipal Corporation Act, 1994

Section 346 sub-section (2) Declaration of controlled area.—

The Director shall not later than six months from the date of declaration under sub-section (1), or within such further period as the State Government may allow, prepare plans showing the controlled area and signifying therein the nature of restriction and conditions proposed to be made applicable to the controlled area and submit the plans to the Government.

10080—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या–38 एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (4क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 2 का संशोधन।

"(4ख) 'कोर क्षेत्र' से अभिप्राय है, इस संशोधन अधिनियम के लागू होने से पचास वर्ष पूर्व योजनाबद्ध या विकसित नगर सीमा के भीतर निर्मित क्षेत्र और जिसे शहरीकरण तथा समय व्यतीत हो जाने के कारण भूमि उपयोग की पुनर्योजना की आवश्यकता है तथा इसमें ग्राम आबादी का निर्मित क्षेत्र भी शामिल है, जिसे नगर सीमा में, बाद में शामिल किया गया है;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 346 का संशोधन।

"(2) निदेशक, उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तिथि से छह मास के अपश्चात् या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो सरकार अनुज्ञात करे, नियन्त्रित क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र को दर्शाते हुए और इसमें नियन्त्रित क्षेत्र में लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्बन्धनों तथा शर्तों के स्वरूप को दर्शाते हुए योजनाएं तैयार करेगा और योजनाओं को सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सरकार द्वारा यथा अधिसूचित योजना मानदण्डों तथा ऐसे प्रभारों के भुगतान तथा वसूली के अध्यधीन, कोर क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग को अनुमत किया जाएगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में नगर पालिका सीमा में और उसके आस पास नियंत्रित क्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रावधान है। इसके अलावा नगर पालिकाओं के आस पास बेतरतीब विकास को विनियमित करने के लिए पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 के तहत नियंत्रित क्षेत्रों की घोषणा और ऐसे नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना के प्रकाशन का प्रावधान है। नगर पालिका शहर के भीतर का क्षेत्र हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा शासित और विनियमित किया जाता है। क्षेत्र की एकीकृत योजना के उद्देश्य से 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों और विकास योजनाओं के प्रस्तावों को नगर पालिका सीमा में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत अपनाया गया है।

नियंत्रित क्षेत्रों व विकास योजनाओं के उपरोक्त स्थिति के साथ मौजूदा शहर को विकास योजना में विभिन्न शब्दों जैसे कि 'मौजूदा शहर'/कोर एरिया/पुराना शहर आदि का प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। चूंकि, 'मौजूदा शहर' बेतरतीब ढंग से विकसित हुए है, इसलिए मौजूदा शहरों में विकास योजना में कोई भूमि उपयोग को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा, जहां नियंत्रित क्षेत्र नगर पालिका सीमा के चारों तरफ घोषित किए गए है, उक्त नगर पालिका सीमा के भीतर खाली पड़े क्षेत्रों को विकास योजनाओं में विभिन्न भूमि उपयोगों में नियत किया गया है, जो कि केवल सलाहकार प्रवृति के है क्योंकि 1963 के अधिनियम के प्रावधान इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते।

इसके अलावा, मौजूदा शहर या कोर क्षेत्र, जो मूल रूप से मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र है, को न तो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 और न ही हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में परिभाषित किया गया है। पारंपरिक रूप से नगर पालिकाओं में भवन योजनाओं को कोर क्षेत्रों में मंजूर करते हुए इसे मिश्रित भू उपयोग प्रकृति का मानती है परंतु किसी भी अधिनियम में कोर क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार कोर क्षेत्र और मिश्रित भूमि उपयोगों पर कोई स्पष्टता नहीं है। इससे ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रस्तावों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की शब्दावली जैसे कि 'मौजूदा शहर'/कोर एरिया/पुराना शहर आदि के कारण भ्रम उत्पन्न होता है।

अतः इस भ्रम को दूर करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन के द्वारा कोर क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए कोर क्षेत्र की परिभाषा और मिश्रित भू उपयोग संबन्धी प्रावधान कोर क्षेत्र में करने की आवश्यकता है।

कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 25 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 से उद्धरण

धारा 346 की उप धारा (2) :–नियन्त्रित क्षेत्र की घोषणा

निदेशक, उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तिथी से छह मास के अपश्चात् या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो सरकार अनुज्ञात करे, नियन्त्रित क्षेत्र को दर्शाते हुए और इसमें नियन्त्रित क्षेत्र में लागू किऐ जाने के लिए प्रस्तावित निर्बन्धनों तथा शर्तों के स्वरूप को दर्शाते हुए योजनाएं तैयार करेगा और योजनाओं को सरकार को प्रस्तुत करेगा।

10080--H.V.S.—H.G.P., Pkl.